भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1431

13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवासन और शहरी मामलों के लिए महाराष्ट्र से प्रस्ताव

1431. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से आवासन और शहरी कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए, अनुमोदित और लंबित प्रस्तावों की कुल संख्या दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार का लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान करने का विचार है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): संविधान के अनुच्छेद 243ब के प्रावधानों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूची के संयोजन में, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/ कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) और एसबीएम-यू 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 और शहरी परिवहन (यूटी) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। इस संबंध में अमृत, एसबीएम-यू, एससीएम और पीएमएवाई-यू के तहत महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त, अनुमोदित और लंबित प्रस्तावों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'आवासन और शहरी मामलों के लिए महाराष्ट्र से प्रस्ताव' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1431 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन:

अमृत के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के लिए 7,759.32 करोड़ रुपए की राज्य वार्षिक कार्य योजनाएँ (एसएएपी) स्वीकृत की गई हैं। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 8,013.28 करोड़ रुपए की लागत वाली 208 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 7,543.14 करोड़ रुपए के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं। इन परियोजनाओं में 4,446.06 करोड़ रुपए की लागत वाली 43 जलापूर्ति परियोजनाएँ, 3,294.03 करोड़ रुपए की लागत वाली 36 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ, 94.06 करोड़ रुपए की लागत वाली एक जल निकासी परियोजना और 179.13 करोड़ रुपए की लागत वाली 128 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएँ शामिल हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, इस मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य में 30,553.59 करोड़ रुपए की 286 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 15,831.02 करोड़ रुपए की 117 जलापूर्ति परियोजनाएं, 12,992.75 करोड़ रुपए की 48 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 1,540.49 करोड़ रुपए की 96 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं और 189.34 करोड़ रुपए की 25 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी:

इस मिशन के अंतर्गत, विभिन्न घटकों के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से 6907.44 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले कुल पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सभी पांच प्रस्तावों को 2495.40 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए अनुमोदन कर दिया गया है।

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम): -

इस मिशन के तहत, महाराष्ट्र से आठ शहरों अर्थात औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नागपुर, नासिक, पिंपरी-चिंचवाड़, पुणे, सोलापुर और ठाणे का चयन किया गया है। 17,044 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 348 परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिनमें से 15,146 करोड़ रुपए की लागत वाली 324 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी:-

महाराष्ट्र राज्य के लिए, कुल 13.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 11.60 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और अब तक 9.33 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। 31.03.2022 की पिछली योजना अवधि को अब 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है (योजना के क्रेडिट आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक को छोड़कर) ताकि फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना सभी स्वीकृत आवास पूरे किए जा सकें। वर्तमान में, इस मिशन के तहत महाराष्ट्र राज्य का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****